Drishti IAS

करेंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश

अक्टूबर 2022

(संग्रह)

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009

Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501

Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

उत्तर प्रदेश 3

- लखनऊ में 8 से 11 अक्टूबर तक होगी इंडियन रोड कॉन्ग्रेस 3
- स्वच्छ सर्वेक्षण 2022: गाज़ियाबाद को मिला प्रदेश में पहला और देश में 12वाँ स्थान 3
- निजी क्षेत्र की फर्मों का उत्तर प्रदेश के हरित ऊर्जा क्षेत्र में 19 हज़ार करोड़ रुपए निवेश करने का प्रस्ताव 4
- निजी क्षेत्र की फर्मों का उत्तर प्रदेश के हरित ऊर्जा क्षेत्र में 19 हज़ार करोड़ रुपए निवेश करने का प्रस्ताव 5
- ग्रेटर नोएडा में होगा अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस कार्यक्रम का आयोजन 5
- केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिये 8 नई परियोजनाओं को मंज़ूरी दी 6
- आईजीआरएस थानों की रैंकिंग में वाराणसी कमिश्नरेट के तीन थाने उत्तर प्रदेश में नंबर वन 7
- उत्तर प्रदेश के हर विकास खंड में एक-एक बागवानी मॉडल गाँव होंगे विकसित 7
- लखनऊ की जागृति यादव एक दिन के लिये बनीं ब्रिटेन की उच्चायुक्त 8
- उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की नई टूरिज़्म पॉलिसी 8
- सीएम योगी को इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड 9
- उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति-2022 9
- लॉजिस्टिक ईज़ में उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुई एचीवर्स की श्रेणी 10
- उत्तर प्रदेश डेयरी विकास एवं दुग्ध उत्पाद संवर्धन नीति-2022 10
- मंत्रिमंडल ने दी नई कपड़ा और परिधान नीति को मंज़ूरी 11
- धान खरीद नीति और उत्तर प्रदेश प्राकृतिक खेती बोर्ड का गठन 11
- जीआई महोत्सव का शुभारंभ 12
- लखनऊ, गाज़ियाबाद, प्रयागराज में कूड़े से बनेगी सीएनजी 13
- उत्तर प्रदेश ने कपड़ा और परिधान नीति की घोषणा की 13
- उत्तर प्रदेश में 15 सीएचसी पीपीपी मोड पर चलेंगे 14
- अब उत्तर प्रदेश में भी मेडिकल की पढ़ाई होगी हिन्दी में 14
- उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति-2022 15
- उत्तर मध्य रेलवे हुआ शत-प्रतिशत विद्युतीकरण वाला देश का पाँचवा ज़ोन 15
- उत्तर प्रदेश के सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक में मेडिक्लेम से मिलेगा कैशलेस इलाज 16
- तराई हाथी अभयारण्य को केंद्र की मंज़ूरी 16
- नोएडा एयरपोर्ट पर देश के सबसे बड़े मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और ओवरहालिंग (एमआरओ) के निर्माण का रास्ता साफ 17
- लंपी वायरस के टीकाकरण में उत्तर प्रदेश देश में अव्वल 18
- उत्तर प्रदेश पुलिस होगी अब हाईटेक 19
- प्लास्टिक कचरा उत्सर्जन में उत्तर प्रदेश आठवें स्थान पर 19
- लखनऊ में एशिया की पहली पैथोजेन रिडक्शन मशीन का लोकार्पण 20
- लखनऊ में होगा इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन 21
- गंगा और उसकी सहायक नदियों का कायाकल्प कर रही राज्य सरकार 21
- उत्तर प्रदेश भारत में शीर्ष इथेनॉल उत्पादक बनने के लिये तैयार 22

नोट :

उत्तर प्रदेश

लखनऊ में 8 से 11 अक्टूबर तक होगी इंडियन रोड कॉन्ग्रेस

चर्चा में क्यों?

30 सितंबर, 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने 8 से 11 अक्टूबर तक लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होने वाले भारतीय सड़क कॉन्ग्रेस (आईआरसी) के 81वें वार्षिक अधिवेशन की तैयारियों की समीक्षा की।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि आखिरी बार ऐसा आयोजन 1985 में लखनऊ में हुआ था, जो आईआरसी का स्वर्ण जयंती सत्र था।
- इस अधिवेशन में आईआरसी नई तकनीक की शुरुआत और सड़कों के रखरखाव पर चर्चा करेगी। देश-विदेश के विभिन्न संस्थानों के सड़क क्षेत्र के विशेषज्ञ नई और कम लागत वाली प्रौद्योगिकियों एवं इस क्षेत्र से जुड़े अन्य मुद्दों पर अपने शोध-पत्र प्रस्तुत करेंगे।
- विदित है कि भारतीय सड़क कॉन्ग्रेस (आईआरसी) देश में राजमार्ग इंजीनियरों की शीर्ष संस्था है। आईआरसी की स्थापना दिसंबर, 1934 में सरकार द्वारा स्थापित जयकर समिति के रूप में विख्यात भारतीय सड़क विकास समिति की सिफारिशों पर की गई थी। इसका उद्देश्य भारत में सड़कों का विकास करना है।
- आईआरसी को औपचारिक रूप से 24 सितंबर, 1937 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया था।
- 1934 में 73 सदस्यों के साथ स्थापित हुई आईआरसी में वर्तमान में 50 लाख से अधिक सहयोगी (प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष) हैं और 17,300 से अधिक पंजीकृत सदस्य हैं, जिनमें केंद्र और राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र, अनुसंधान संस्थान, स्थानीय निकाय, निजी क्षेत्र, ग्राही, ठेकेदार, सलाहकार, उपकरण निर्माता, मशीनरी निर्माता, सामग्री निर्माता और आपूर्तिकर्त्ता, औद्योगिक संघ, विश्व बैंक, एडीबी, जेआईसीए, जेआरए, आईआरएफ आदि जैसे बहुपक्षीय और संस्थागत संगठनों से सड़क क्षेत्र के सभी हितधारकों के इंजीनियर और व्यवसायी शामिल हैं।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2022: गाज़ियाबाद को मिला प्रदेश में पहला और देश में 12वाँ स्थान

चर्चा में क्यों?

1 अक्टूबर, 2022 को जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की रैंकिंग में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को पीछे छोड़ गाज़ियाबाद ने प्रदेश में पहला और देश में 12वाँ स्थान प्राप्त किया है।

प्रमुख बिंदु

- यह गाज़ियाबाद की अब तक की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। इससे पहले वर्ष 2021 में उत्तर प्रदेश में गाज़ियाबाद दूसरे नंबर पर और देश में 18वें नंबर पर रहा था। 16 लाख से अधिक आबादी वाले गाज़ियाबाद को थ्री स्टार रेटिंग मिली है और ओडीएफ प्लस घोषित किया गया है।
- 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में गाज़ियाबाद के बाद मेरठ, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, आगरा और कानपुर का नंबर है।
- देश के शीर्ष 15 स्वच्छ शहरों में उत्तर प्रदेश के 75 ज़िलों में सिर्फ गाज़ियाबाद और मेरठ शामिल हैं। गाज़ियाबाद 12वें और मेरठ 15वें नंबर पर है। वहीं पहले नंबर पर इंदौर रहा।
- इसी तरह एक लाख से 10 लाख की आबादी वाले शहर में नोएडा देश में पाँचवे और प्रदेश में पहले नंबर पर है। प्रदेश में अलीगढ़ दूसरे, मथुरा तीसरे, फिरोज़ाबाद चौथे और गोंडा पाँचवे स्थान पर है। एक लाख से 10 लाख की कैटगरी वाले शहरों में नोएडा, अलीगढ़ और मथुरा के अलावा कोई भी शहर टॉप 100 में जगह नहीं बना पाया है।

नोट :

- ओवरऑल रैंकिंग में उत्तर प्रदेश की स्थिति पिछले वर्ष की तुलना में बिगड़ी है। 2021 के सर्वेक्षण में यूपी का स्थान छठा था, जबकि 2022 के सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश का स्थान 10वाँ आया है।
- एक लाख से कम आबादी वाले शहरों में बिजनौर को सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर में पहला स्थान मिला, वहीं एक लाख से अधिक आबादी वाले गंगा शहरों में वाराणसी को दूसरा स्थान मिला।
- बेस्ट सिटी फॉर इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेज में लखनऊ कैंटोनमेंट बोर्ड को चुना गया है।
- प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने बताया कि प्रदेश को इस वर्ष कुल 13 पुरस्कार हासिल हुए हैं। इनमें तीन नगर निगम, चार नगर पालिका परिषद और तीन नगर पंचायते हैं। इनमें नगर निगम लखनऊ, कानपुर नगर और मेरठ शामिल हैं।

निजी क्षेत्र की फर्मों का उत्तर प्रदेश के हरित ऊर्जा क्षेत्र में 19 हज़ार करोड़ रुपए निवेश करने का प्रस्ताव

चर्चा में क्यों?

3 अक्टूबर, 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि निजी क्षेत्र की फर्मों ने राज्य के हरित ऊर्जा क्षेत्र में लगभग 19,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का प्रस्ताव दिया है।

प्रमुख बिंदु

- इन प्रस्तावों में ग्रीनको और जेएसडब्ल्यू ग्रुप द्वारा विभिन्न अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं में क्रमशः लगभग 13,000 करोड़ रुपए और 5,900 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। यह पहली बार है कि उत्तर प्रदेश सरकार को घरेलू हरित ऊर्जा क्षेत्र में इतने बड़े निवेश प्रस्ताव मिले हैं।
- आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, राज्य 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा में 450 गीगावाट (जीडब्ल्यू) और गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता में 500 गीगावाट प्राप्त करने के केंद्र के व्यापक लक्ष्य के साथ संरेखित कर रहा है। यह अपने अंतर्राष्ट्रीय जलवायु और हरित ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने के लिये भारत की प्रतिबद्धता का हिस्सा है।
- हरित ऊर्जा भविष्य में कार्बन उत्सर्जन को कम करने और पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में प्रमुख भूमिका निभाएगा।
- अगले साल मेगा यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के लिये राज्य सरकार हरित ऊर्जा सहित कई क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की कंपनियों को लुभाने के लिये सभी प्रयास कर रही है। राज्य जनवरी 2023 में घरेलू और बहुराष्ट्रीय कंपनियों (एमएनसी) से नए निवेश प्रस्तावों में 10 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य बना रहा है।
- शिखर सम्मेलन को गति देने के लिये राज्य ने अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, संयुक्त अरब अमीरात, स्वीडन, सिंगापुर, नीदरलैंड, इजराइल, फ्राँस, जर्मनी, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया सहित प्रमुख देशों में रोड शो आयोजित करने की योजना बनाई है।
- पिछले छह महीनों में राज्य ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों सहित 55 निजी क्षेत्र की कंपनियों से 45,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश प्रस्ताव प्राप्त करने का दावा किया है। इनमें हरित ऊर्जा क्षेत्र की परियोजनाएँ शामिल हैं।
- कॉसिस ग्रुप ने ग्रीन मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट्स में 6,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का प्रस्ताव दिया है, जबकि वरुण बेवरेजेज चार अलग-अलग बेवरेज प्रोजेक्ट्स में लगभग 3,600 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। इसी तरह जेके पेंट्स और कीयान डिस्टिलरीज अपनी परियोजनाओं में क्रमशः 600 करोड़ रुपए और 500 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी।
- सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र ने पिछले पाँच वर्षों में लगभग 95,000 करोड़ रुपए के अधिकतम निवेश प्रस्तावों को हासिल किया है। इनमें लगभग 20,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश प्रोफाइल के साथ डेटा सेंटर स्पेस में सात परियोजनाएँ शामिल हैं। इनमें से पांच परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है, शेष दो को जल्द ही राज्य कैबिनेट की मंजूरी मिलने की उम्मीद है।

निजी क्षेत्र की फर्मों का उत्तर प्रदेश के हरित ऊर्जा क्षेत्र में 19 हज़ार करोड़ रुपए निवेश करने का प्रस्ताव

चर्चा में क्यों ?

3 अक्टूबर, 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि निजी क्षेत्र की फर्मों ने राज्य के हरित ऊर्जा क्षेत्र में लगभग 19,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का प्रस्ताव दिया है।

प्रमुख बिंदु

- इन प्रस्तावों में ग्रीनको और जेएसडब्ल्यू ग्रुप द्वारा विभिन्न अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं में क्रमश: लगभग 13,000 करोड़ रुपए और 5,900 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। यह पहली बार है कि उत्तर प्रदेश सरकार को घरेलू हरित ऊर्जा क्षेत्र में इतने बड़े निवेश प्रस्ताव मिले हैं।
- आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, राज्य 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा में 450 गीगावाट (जीडब्ल्यू) और गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता में 500 गीगावाट प्राप्त करने के केंद्र के व्यापक लक्ष्य के साथ संरेखित कर रहा है। यह अपने अंतर्राष्ट्रीय जलवायु और हरित ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने के लिये भारत की प्रतिबद्धता का हिस्सा है।
- हरित ऊर्जा भविष्य में कार्बन उत्सर्जन को कम करने और पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में प्रमुख भूमिका निभाएगा।
- अगले साल मेगा यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के लिये राज्य सरकार हरित ऊर्जा सहित कई क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की कंपनियों को लुभाने के लिये सभी प्रयास कर रही है। राज्य जनवरी 2023 में घरेलू और बहुराष्ट्रीय कंपनियों (एमएनसी) से नए निवेश प्रस्तावों में 10 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य बना रहा है।
- शिखर सम्मेलन को गति देने के लिये राज्य ने अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, संयुक्त अरब अमीरात, स्वीडन, सिंगापुर, नीदरलैंड, इजराइल, फ्रांँस, जर्मनी, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया सहित प्रमुख देशों में रोड शो आयोजित करने की योजना बनाई है।
- पिछले छह महीनों में राज्य ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों सहित 55 निजी क्षेत्र की कंपनियों से 45,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश प्रस्ताव प्राप्त करने का दावा किया है। इनमें हरित ऊर्जा क्षेत्र की परियोजनाएंँ शामिल हैं।
- कॉसिस ग्रुप ने ग्रीन मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट्स में 6,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का प्रस्ताव दिया है, जबकि वरुण बेवरेजेज चार अलग-अलग बेवरेज प्रोजेक्ट्स में लगभग 3,600 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। इसी तरह जेके पेंट्स और कीयान डिस्टिलरीज अपनी परियोजनाओं में क्रमश: 600 करोड़ रुपए और 500 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी।
- सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र ने पिछले पाँच वर्षों में लगभग 95,000 करोड़ रुपए के अधिकतम निवेश प्रस्तावों को हासिल किया है। इनमें लगभग 20,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश प्रोफाइल के साथ डेटा सेंटर स्पेस में सात परियोजनाएंँ शामिल हैं। इनमें से पांच परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है, शेष दो को जल्द ही राज्य कैबिनेट की मंजूरी मिलने की उम्मीद है।

ग्रेटर नोएडा में होगा अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस कार्यक्रम का आयोजन

चर्चा में क्यों ?

5 अक्टूबर, 2022 को उत्तर प्रदेश के संस्कृति मंत्रालय ने राज्य के ग्रेटर नॉएडा के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय (जीबीयू) में नौ अक्टूबर को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस कार्यक्रम होने की जानकारी दी।

प्रमुख बिंदु

- जानकारी के अनुसार राज्य सरकार के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा।
- बुद्ध धर्म के अनुयायी करीब 20 देशों के प्रतिनिधि और राजदूत के कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना है तथा गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय (जीबीयू) के कुलाधिपति व राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे।
- अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस के मौके पर वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, चीन, दक्षिण कोरिया, भूटान, ताइवान, रोमानिया, कोरिया, अफगानिस्तान, नेपाल, मंगोलिया, म्यांमार, श्रीलंका और अमेरिका के प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं। इन्हीं देशों के सर्वाधिक छात्र गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने के लिये आते हैं।

नोट :

- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने 2017 में पहली विदेश यात्रा बुद्ध धर्म के अनुयायी म्यांमार (बर्मा) की ही की थी।
- गौरतलब है कि भगवान बुद्ध के नाम पर देश का इकलौता विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध नगर ज़िले में है। राज्य के साथ देश के विभिन्न विश्वविद्यालय में बुद्ध स्टडीज की पढ़ाई होती है, लेकिन विदेशी छात्रों का सर्वाधिक रुझान गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय को लेकर है। वर्तमान में 15 देशों के छात्र बौद्ध स्टडीज के लिये प्रतिवर्ष गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय का रुख करते हैं।
- एनसीआर में भी गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय बुद्धिस्ट का केंद्र है। बुद्ध स्टडीज का केंद्र पूर्व में दिल्ली में था, लेकिन गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न कोर्स, बुद्ध संकाय के साथ बौद्ध स्टडीज में बीए, एमए, पीएचडी, बौद्ध पर्यटन, पालि भाषा व साहित्य में डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स के कारण छात्रों में इसके प्रति रुझान अधिक है।
- ज्ञातव्य है कि अभिधम्म दिवस असल में बौद्ध भिक्षुओं के लिये तीन महीने की वर्षा वापसी (वर्षावास या वासा की समाप्ति का प्रतीक) है, जिसके दौरान वे एक स्थान पर रहते हैं और प्रार्थना करते हैं। अभिधम्म दिवस ज्यादातर उन देशों में मनाया जाता है, जहाँ की अधिकांश आबादी बौद्ध धर्म की अनुयायियों की हैं। मान्यता के अनुसार, इसी दिन भगवान बुद्ध स्वर्ग से पृथ्वी पर वापस आए थे।

केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिये 8 नई परियोजनाओं को मंज़ूरी दी

चर्चा में क्यों?

7 अक्टूबर, 2022 को उत्तर प्रदेश के एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि केंद्र सरकार ने स्वच्छ गंगा परियोजना के लिये राष्ट्रीय मिशन के तहत राज्य में सीवरेज प्रबंधन सहित आठ नई परियोजनाओं को मंज़ूरी दी है।

प्रमुख बिंदु

- प्रवक्ता ने बताया कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की कार्यकारी समिति की 45वीं बैठक में सीवेज प्रबंधन के लिये चार परियोजनाओं को मंज़ूरी दी गई है, जिनमें एक वाराणसी में भी है।
- इस परियोजना में अस्सी नल्ला (Assi Nullah) के दोहन के लिये 55 एमएलडी क्षमता के एसटीपी का निर्माण भी शामिल है। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 09 करोड़ रुपए है।
- सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि वाराणसी की परियोजना का लक्ष्य तीन नालों - अस्सी, सामने घाट और नखी से शून्य अनुपचारित निर्वहन के लक्ष्य को प्राप्त करना है।
- अन्य परियोजनाओं में 13 एमएलडी एसटीपी का निर्माण और मौजूदा संरचनाओं का नवीनीकरण शामिल हैं। मथुरा-वृंदावन की इन परियोजनाओं में यमुना नदी को प्रदूषित करने वाले 11 नालों को अवरुद्ध और मोड़ने की परिकल्पना की गई है। वृंदावन और मथुरा के कोसी कलां में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का निर्माण किया जाएगा।
- चार ज़िलों- हापुड़, बुलंदशहर, बदायूँ और मिर्ज़ापुर में जैव-विविधता पार्क स्थापित करने की एक बड़ी परियोजना को भी मंज़ूरी दी गई है। इनके नाम हैं मिर्ज़ापुर में मोहनपुर बायोडायवर्सिटी पार्क, बुलंदशहर में रामघाट बायोडायवर्सिटी पार्क, हापुड़ में आलमगीरपुर बायोडायवर्सिटी पार्क और बदायूँ में उझानी बायोडायवर्सिटी पार्क।
- प्रवक्ता ने कहा कि ये चारों स्थान गंगा नदी के बाढ़ के मैदानों पर स्थित हैं। प्रस्तावित पार्क गंगा के बाढ़ के मैदानों के साथ आरक्षित वनों का हिस्सा हैं और नदी के कायाकल्प एवं जैव-विविधता संरक्षण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
- जैव-विविधता पार्क देशी पौधों और जानवरों की प्रजातियों के संयोजन के साथ जंगल को अद्वितीय परिदृश्य प्रदान करेंगे, जिससे एक क्षेत्र में बनाए गए आत्मनिर्भर जैविक समुदायों का निर्माण होगा। गंगा जैव-विविधता पार्कों का समग्र परिणाम पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं, जैव-विविधता और गंगा नदी के कायाकल्प को बेसिन पैमाने पर बनाए रखने में मदद करेगा।

आईजीआरएस थानों की रैंकिंग में वाराणसी कमिश्नरेट के तीन थाने उत्तर प्रदेश में नंबर वन

चर्चा में क्यों ?

7 अक्टूबर, 2022 को वाराणसी के पुलिस आयक्त ए. सतीश गणेश ने बताया कि आईजीआरएस थानों की रैंकिंग में कमिश्नरेट वाराणसी के तीन थाने शत-प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रदेश में पहले स्थान पर आए हैं।

प्रमुख बिंदु

- पुलिस आयुक्त ए. सतीश गणेश के अनुसार आईजीआरएस निस्तारण रैंकिंग में कमिश्नरेट वाराणसी के सिगरा, आदमपुर और दशाश्वमेध थाने को प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इन तीनों थाने के प्रभारियों को प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा।
- पुलिस आयुक्त ने कहा कि आईजीआरएस की रैंकिंग में एकदम निचले पायदान पर आने वाले तीन थानों - कोतवाली, चितईपुर और पर्यटक की खराब रैंकिंग के कारणों की समीक्षा डीसीपी स्तर के अधिकारी से कराई जाएगी। लापरवाही पाए जाने पर थाना प्रभारियों पर कार्यवाही भी तय है। तीनों प्रभारियों को चेतावनी नोटिस जारी की गई है।
- उत्तर प्रदेश सरकार की ऑनलाइन शिकायत प्रणाली जन-सुनवाई पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में वाराणसी के थाने प्रदेश भर में अव्वल हैं।
- जन-सुनवाई पोर्टल से प्राप्त शिकायतों को पुलिस कार्यालय में गठित आईजीआरएस सेल संबंधित थानों के लिये ऑनलाइन प्रेषित करती है। थाना प्रभारी प्राप्त संदर्भों की जाँच ऑनलाइन दिये गए समय के अनुसार संबंधित को प्रेषित करते हैं। जन-सुनवाई पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का आईजीआरएस सेल के अधिकारी और कर्मचारी समाधान करते हैं।

उत्तर प्रदेश के हर विकास खंड में एक-एक बागवानी मॉडल गाँव होंगे विकसित

चर्चा में क्यों ?

9 अक्टूबर, 2022 को उत्तर प्रदेश के उद्यान एवं कृषि निर्यात राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह ने लखनऊ के उद्यान भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभागीय समीक्षा के दौरान अधिकारियों को राज्य की सभी ग्राम पंचायतों तक बागवानी विकास के कार्यक्रमों को पहुँचाने के मकसद से प्रत्येक विकासखंड में एक-एक बागवानी मॉडल गाँव विकसित करने का निर्देश दिया।

प्रमुख बिंदु

- उद्यान एवं कृषि निर्यात राज्यमंत्री ने बताया कि प्रत्येक मॉडल गाँव का उपनिदेशक और डीएचओ स्तर के अधिकारी निरीक्षण करेंगे। साथ ही, जानकारी के लिये मॉडल गाँव के बाहर फ्लैक्स बोर्ड लगाए जाएंगे। इस बोर्ड में दर्शाया जाएगा कि संबंधित गाँव को मॉडल विलेज के रूप में चिह्नित किया गया है।
- उन्होंने निर्देश दिये कि विभाग की रिक्त उपजाऊ भूमि पर आलू, बीज उत्पादन कार्यक्रम को बढ़ाने के लिये विभागीय फार्म हाउस व उत्पादन इकाइयों के पूर्ण विवरण के साथ परिसंपत्तियों के लिये पंजिका अनुरक्षित की जाए तथा उद्यान विभाग की ऐसी भूमि और भवन, जो राजस्व के अभिलेखों में अंकित नहीं हैं, उसे अंकित कराने का कार्य किया जाए।
- उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि नवोन्मेषी कार्यक्रमों के तहत ड्रैगन फ्रूट, स्ट्राबेरी आदि फसलों का क्षेत्र विस्तार करते हुए गुणात्मक उत्पादन को बढ़ाने पर ज़ोर दिया जाए। किसानों को मंडी के पास कोल्ड रूम बनाने के लिये प्रोत्साहित किया जाए।
- उन्होंने निर्देश दिये कि 'पर ड्राप-मोर-क्रॉप'के तहत कम प्रगति वाले ज़िलों को सप्ताहवार लक्ष्य देकर समीक्षा की जाए। 20 अक्टूबर तक रबी की फसल के बीज वितरित कर दिये जाएँ।
- कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि विभागीय योजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करते हुए बागवानी विकास के सभी आयामों को समेकित एवं क्लस्टर के रूप में विकसित किया जाए। सभी उपनिदेशक और उद्यान अधिकारी अपने ज़िले में होने वाली औद्यानिक फसलें कितनी मात्रा में हो रही हैं, उसकी रिपोर्ट उपलब्ध कराएँ।
- समीक्षा बैठक में मधुमक्खी पालन के विकास के लिये एक विशिष्ट सेंटर आफ एक्सीलेन्स, लखनऊ में एवं संरक्षित खेती के तहत लखनऊ, बाराबंकी, कानपुर, हापुड़ को चिह्नित कर पाली हाउस/शेडनेट हाउस की स्थापना कराने का निर्णय लिया गया।

नोट :

लखनऊ की जागृति यादव एक दिन के लिये बनीं ब्रिटेन की उच्चायुक्त

चर्चा में क्यों ?

10 अक्टूबर, 2022 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ की 20 वर्षीय जागृति यादव 'एक दिन के लिये उच्चायुक्त प्रतियोगिता के भारत संस्करण' में भारत में एक दिन के लिये ब्रिटिश उच्चायोग में उच्चायुक्त बनीं।

प्रमुख बिंदु

- ब्रिटिश दूतावास ने बताया कि जागृति यादव एक दिन के लिये उच्चायुक्त प्रतियोगिता के भारत संस्करण की छठवीं विजेता हैं।
- जागृति यादव ने एक दिन के लिये उच्चायुक्त प्रतियोगिता का छठा संस्करण जीतने के बाद भारत में ब्रिटेन के शीर्ष राजनयिक के रूप में एक दिन बिताया। जागृति ने राजनयिक गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला का भी अनुभव किया, जिसमें विभिन्न स्टेकहोल्डर्स के साथ बैठक की। इस दौरान जागृति कई कार्यक्रमों में भी शामिल हुईं।
- विदित है कि वर्ष 2017 से सालाना इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य महिलाओं को अगली पीढ़ी के लिये सशक्त बनाना है।
- भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, प्रोफेसर अजय कुमार सूद के साथ, जागृति ने स्टीम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, कला और गणित) में 75 भारतीय महिलाओं को सम्मानित करने वाली एक पुस्तक भी लॉन्च की।
- ब्रिटेन के उच्चायुक्त एलेक्स एलिस ने कहा कि जागृति मुखर और केंद्रित हैं तथा पूरे भारत में प्रतिभा दिखाती हैं। जैसे-जैसे महिलाएँ बढ़ती हैं, हम सब उठते हैं। ब्रिटेन और भारत अनुसंधान और शिक्षा सहित लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिये एक साथ बहुत कुछ करते हैं। उन्होंने बताया कि इस साल भारत के लिये शेवनिंग छात्रवृत्ति का 50 प्रतिशत महिलाओं को प्रदान किया गया है।
- उल्लेखनीय है कि उच्चायोग अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस (11 अक्टूबर) को मनाने के लिये हर साल 'एक दिन के लिये उच्चायुक्त' प्रतियोगिता का आयोजन करता है। इस साल की प्रतियोगिता के लिये पूरे भारत से 270 से अधिक लड़कियों ने आवेदन किया था।

उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की नई टूरिज्म पॉलिसी

चर्चा में क्यों ?

12 अक्टूबर, 2022 को उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश मेश्राम ने बताया कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राज्य के पर्यटन विभाग ने आकर्षक नई टूरिज्म पॉलिसी तैयार की है।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि विभाग द्वारा तैयार की गई पर्यटन नीति-2022 के प्रारूप में राज्य को एक ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने पर फोकस करते हुए कई नए क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है।
- इस पॉलिसी में राज्य को वैवाहिक पर्यटन के डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की भी योजना है यानि राज्य के टूरिस्ट डेस्टिनेशन अब शादी को भी यादगार बनाएंगे। देसी और विदेशी जोड़ों के विवाह को यादगार बनाने के लिये होटल, किलों और पर्यटक स्थलों को विकसित किया जाएगा। इसके लिये वेडिंग प्लानरों और इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों की मदद ली जाएगी।
- हर साल बड़े पैमाने पर विदेशी मेहमानों का शादी के लिये भारत में वाराणसी और आगरा में आने को ध्यान में रखते हुए विभाग ने यह खाका तैयार किया है।
- वेडिंग प्लानरों और इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों की मदद से वाराणसी, आगरा, मथुरा-वृंदावन एवं चुनार, वॉटर फॉल आदि को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही प्री वेडिंग के लिये कपल्स को प्री शूट की सुविधा भी दी जाएगी।
- राज्य में कई ऐसी ऐतिहासिक विरासत स्थल हैं जो वन विभाग के अधीन आती हैं। ऐसे में इन जगहों को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिये वन विभाग की भी मदद ली जाएगी।

- जहाँ पर सबसे ज्यादा विदेशी मेहमान शादी के बंधन में बंधने के लिये आते हैं, उन जगहों को और आकर्षक बनाने के लिये इवेंट कंपनी से सुझाव मांगे जाएंगे। वेडिंग डेस्टीनेशनों को सूचीबद्ध करके इनका ऑनलाइन प्रचार-प्रसार भी किया जाएगा। पर्यटन विभाग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इसे प्रमोट करेगा।
- पर्यटन प्रमुख सचिव मुकेश मेश्राम ने कहा कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश विदेशी जोड़ों के लिये राजसी ठाठ-बाट और सांस्कृतिक विरासत के आधार पर विवाह के लिये बेहतरीन जगह है। ऐसे में राज्य के विभिन्न शहरों में वेडिंग डेस्टिनेशन के लिये उपयुक्त स्थानों को चिह्नित किया जा रहा है। इसके प्रचार-प्रसार के लिये वेडिंग प्लानरों और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की मदद ली जाएगी।

सीएम योगी को इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड

चर्चा में क्यों?

12 अक्टूबर, 2022 को मीडिया समूह द्वारा आयोजित 'इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड' समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 'इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड' से सम्मानित किया गया।

प्रमुख बिंदु

- इस समारोह में अवार्डों की श्रृंखला में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को राजनीति श्रेणी में उनके शानदार काम के लिये यह सम्मान मिला है। हालाँकि इस अवार्ड समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मौज़ूद नहीं हो सके थे। उन्होंने इस अवार्ड को राज्य की 25 करोड़ जनता को समर्पित किया।
- मीडिया समूह द्वारा आयोजित इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड समारोह में मनोरंजन, राजनीति, खेल, स्टार्टअप, सोशल चेंज और जलवायु आदि श्रेणियों में प्रेरणास्पद कार्य करने वाली भारतीय हस्तियों को सम्मानित किया गया है।
- इस श्रेणी में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया सहित कई बड़े नाम शामिल थे।

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति-2022

चर्चा में क्यों?

13 अक्टूबर, 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य में पर्यावरण संरक्षण के लिये इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के प्रति लोगों का रुझान बढ़ाने तथा निर्माता कंपनियों को आकर्षित करने हेतु उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति-2022 को मंज़ूरी दी गई।

प्रमुख बिंदु

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति-2022 में उपभोक्ताओं, निर्माताओं तथा चार्जिंग व बैट्री स्वैपिंग सेवा प्रदाताओं के हितों का ध्यान रखा गया है। यह नीति अगले 5 वर्षों के लिये प्रभावी रहेगी।

- नीति की प्रभावी अवधि में हर ज़िले में कम-से-कम 20 चार्जिंग स्टेशन व पाँच स्वैपिंग स्टेशन स्थापित करने के लिये निवेशकों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिये निवेश के समन्वय व सुविधा के लिये 'इन्वेस्ट यूपी' को नोडल एजेंसी बनाया जाएगा।
- चार्जिंग इंप्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिये सभी स्वीकृतियाँ अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में प्राधिकृत समिति इन्वेस्ट यूपी की अनुशंसा पर दी जाएंगी।
- ज्ञातव्य है कि राज्य में निवेश बढ़ाने के लिये ईवी निर्माता कंपनियों तथा बैट्री व संबंधित उपकरण निर्माताओं के साथ उपभोक्ताओं के लिये नई नीति में 500 करोड़ रुपए के बजट की व्यवस्था की गई हैं।
- राज्य के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि नीति का लक्ष्य 50 हज़ार करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने के साथ ही 1 लाख लोगों को परोक्ष रूप से रोज़गार उपलब्ध कराना है।

- राज्य में बने सभी श्रेणी के ईवी खरीदने पर नई नीति के प्रभावी होने की तिथि से पाँच वर्षों तक उपभोक्ताओं को रोड टैक्स व पंजीकरण शुल्क नहीं देना होगा, जबकि राज्य में खरीदे गए व पंजीकृत सभी ईवी पर नीति के लागू होने की तिथि से तीन वर्षों तक रोड टैक्स व पंजीकरण शुल्क में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी।
- इस नीति में यूपी में खरीदे गए ईवी को फैक्ट्री मूल्य पर 15 प्रतिशत की सब्सिडी दिये जाने का भी निर्णय लिया गया है।
- इस नीति से राज्य में एक गीगावाट की न्यूनतम क्षमता वाले बैट्री निर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिये 1500 करोड़ रुपए या उससे अधिक निवेश करने वाली पहली दो अल्ट्रा मेगा बैट्री परियोजनाओं के लिये अधिकतम 1000 करोड़ रुपए परियोजना के निवेश पर 30 प्रतिशत की दर से पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- इसके अलावा इस नीति में रिसर्च एंड डेवलपमेंट तथा परीक्षण सुविधाओं समेत ईवी, ईवी बैट्री व उनसे जुड़े उपकरणों की एकीकृत निर्माण सुविधा स्थापित करने के लिये 3000 करोड़ रुपए या उससे अधिक का निवेश करने वाली पहली दो एकीकृत ईवी परियोजनाओं को अधिकतम 30 प्रतिशत की दर से पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

लॉजिस्टिक ईज़ में उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुई एचीवर्स की श्रेणी

चर्चा में क्यों?

13 अक्टूबर, 2022 को उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग की तरफ से लॉजिस्टिक ईज़ एक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स (लीड्स) की जारी हुई सर्वे रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश को एचीवर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है।

प्रमुख बिंदु

- लॉजिस्टिक ईज़ मामले में उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे 15 राज्यों को भी एचीवर्स की श्रेणी में रखा गया है।
- केरल, मध्य प्रदेश और राजस्थान को एचीवर्स की ओर बढ़ते राज्यों की श्रेणी प्राप्त हुई है।
- बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ राज्यों को आकांक्षी राज्यों की श्रेणी में शामिल किया गया है।
- उल्लेखनीय है कि देश में राज्यों के बीच लॉजिस्टिक सुविधा को लेकर प्रतिस्पर्धा का माहौल पैदा करने के लिये लीड्स सर्वे कराया जाता है। यह सर्वे लॉजिस्टिक सुगमता, लागत और अन्य संबंधित आँकड़ों को जुटाकर किया जाता है।
- विदित है कि हाल ही में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पॉलिसी भी जारी की गई है, ताकि भारत में लॉजिस्टिक लागत को 8–9% तक लाया जा सके।

उत्तर प्रदेश डेयरी विकास एवं दुग्ध उत्पाद संवर्धन नीति-2022

चर्चा में क्यों?

13 अक्टूबर, 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति-2018 को समाप्त कर 'उत्तर प्रदेश डेयरी विकास एवं दुग्ध उत्पाद संवर्धन नीति-2022' को मंज़ूरी दी।

प्रमुख बिंदु

- उत्तर प्रदेश डेयरी विकास एवं दुग्ध उत्पाद संवर्धन नीति-2022 अधिसूचना जारी होने की तारीख से पाँच साल के लिये प्रभावी होगी।
- इसका मुख्य उद्देश्य निवेशकों की सुविधा के लिये प्रक्रियाओं के सरलीकरण द्वारा राज्य में दूध आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करना है। दुग्ध प्रसंस्करण के स्तर को बढ़ाने के लिये अगले पाँच वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश का लक्ष्य रखा गया है।
- प्रस्तावित नीति में प्रदेश के विभिन्न एफपीओ, सहकारी संस्थाओं और निजी क्षेत्र के उद्यमियों को नई दुग्ध प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पाद बनाने वाली डेयरी इकाईयाँ उपलब्ध कराई जाएंगी। विनिर्माण इकाइयों की स्थापना और क्षमता विस्तार (मौजूदा क्षमता में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि) का प्रस्ताव किया गया है।
- नई नीति के तहत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 1.25 लाख नए रोज़गार सृजित होने का अनुमान है।

मंत्रिमंडल ने दी नई कपड़ा और परिधान नीति को मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

13 अक्टूबर, 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश को कपड़ा हब बनाने हेतु इस क्षेत्र में निजी निवेश आकर्षित करने और सभी इकाइयों का विकास सुनिश्चित करने के लिये एक नई कपड़ा और परिधान नीति को मंज़ूरी दी गई।

प्रमुख बिंदु

- मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एंड गारमेंटिंग पॉलिसी-2022 को मंज़ूरी दी है तथा इसमें किसी भी तरह का संशोधन करने के लिये मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है।
- नई नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य को वैश्विक स्तर के परिधान निर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना और कपड़ा उद्योग से संबंधित सभी प्रकार की इकाइयों, जैसे- हथकरघा, पावरलूम, कताई, बुनाई, प्रसंस्करण और परिधान का सतत् विकास करना है।
- नीति का विशिष्ट उद्देश्य कपड़ा और परिधान क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपए के निजी निवेश को आकर्षित करना, पाँच लाख लोगों के लिये रोज़गार के अवसर पैदा करना, निजी क्षेत्र में पाँच कपड़ा और परिधान पार्क विकसित करना तथा हथकरघा और पावरलूम बुनकर की आय में वृद्धि करना है।
- संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि उत्तर प्रदेश की कपड़ा एवं परिधान नीति-2022 में कपड़ा क्षेत्र में निवेश करने वाली इकाइयों को निवेश आकर्षित कर रोज़गार पैदा करने के उद्देश्य से विभिन्न मदों में वित्तीय सुविधाओं के साथ विशेष प्रोत्साहन देने का प्रावधान था।
- यह नीति प्रख्यापन की तारीख से पाँच साल के लिये प्रभावी होगी। इस नीति से राज्य में निवेश बढ़ेगा और तीन लाख रोज़गार के अवसर पैदा होने की संभावना है।
- नई नीति के तहत कपड़ा और वस्त्र इकाइयों को संयंत्र एवं मशीनरी की खरीद पर किये गए निवेश पर 25 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- इसके अलावा प्रदेश के मध्यांचल क्षेत्र में स्थापित होने वाली कपड़ा एवं वस्त्र इकाईयों को 5 प्रतिशत की दर से और पूर्वांचल एवं बुंदेलखंड में स्थापित होने वाली कपड़ा और वस्त्र इकाइयों को 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त पूंजीगत अनुदान की प्रतिपूर्ति की जाएगी। पूंजीगत सब्सिडी की सीमा प्रति यूनिट 100 करोड़ रुपए तक सीमित होगी।

धान खरीद नीति और उत्तर प्रदेश प्राकृतिक खेती बोर्ड का गठन

चर्चा में क्यों ?

13 अक्टूबर, 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में बारिश और बाढ़ की मार झेल रहे किसानों को राहत देने के उद्देश्य से 'धान खरीद नीति' की घोषणा सहित कृषि क्षेत्र के लिये कई तरह की छूट और राज्य में 'उत्तर प्रदेश प्राकृतिक खेती बोर्ड' के गठन का फैसला लिया गया।

प्रमुख बिंदु

- कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के अनुसार, राज्य मंत्रिमंडल ने नई धान खरीद नीति की घोषणा की है, जिसके तहत सामान्य ग्रेड धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,040 रुपए प्रति क्विंटल और ए ग्रेड धान का 2,060 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है।
- कृषि मंत्री ने बताया कि हरदोई, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़ और झाँसी ज़िलों में धान खरीदी की अवधि 1 अक्टूबर से 31 जनवरी तक है और रायबरेली, उन्नाव, चित्रकूट, कानपुर, अयोध्या, बस्ती, गोरखपुर, आज़मगढ़, वाराणसी, मिर्ज़ापुर तथा प्रयागराज के लिये यह अवधि 1 नवंबर से 28 फरवरी तक है।
- उन्होंने कहा कि धान खरीद के लिये ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है और किसानों से सभी खरीद कंप्यूटर सत्यापित खतौनी और आधार कार्ड के आधार पर की जाएगी। क्रय केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ परचेज मशीनों के माध्यम से किसानों के बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण द्वारा धान की खरीद की जाएगी।

- धान की खरीद खाद्य विभाग, पीसीएफ, पीसीयू, मंडी परिषद, यूपीएस और भारतीय खाद्य निगम जैसी छह एजेंसियों के 4,000 खरीद केंद्रों के माध्यम से की जाएगी।
- धान की खरीद के 48 घंटे के भीतर भारत सरकार के पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से सभी क्रय एजेंसियों द्वारा धान की कीमत का भुगतान किया जाएगा।
- कैबिनेट ने मूल्य समर्थन योजना के तहत मोटे अनाज (मक्का और बाजरा) के लिये खरीद नीति तैयार करने के प्रस्ताव को भी मंज़ूरी दी है।
- इस नीति के तहत मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,962 रुपए प्रति क्विंटल और बाजरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,350 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। मक्का और बाजरा की खरीद की अवधि 15 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक होगी।
- मक्का बुलंदशहर, हापुड़, बदायूँ, अलीगढ़, एटा, कासगंज, फिरोज़ाबाद, मैनपुरी, हरदोई, उन्नाव, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कन्नौज, फर्रुखाबाद, इटावा, औरैया, गोंडा, बहराइच श्रावस्ती, बलिया, जौनपुर, देवरिया, सोनभद्र और ललितपुर ज़िलों से, जबकि बाजरा बुलंदशहर, बरेली, बदायूँ, संभल, अलीगढ़, एटा, कासगंज, हाथरस, आगरा, मथुरा, मैनपुरी, फिरोज़ाबाद, कानपुर देहात, इटावा, औरैया, गाज़ीपुर, जालौन और प्रयागराज ज़िलों से खरीदा जाएगा।
- मक्का और बाजरा की बिक्री के लिये सभी क्रय एजेंसियों पर किसान पंजीकरण और ऑनलाइन खरीद अनिवार्य कर दी गई है। किसानों से मक्का और बाजरा की खरीद कंप्यूटर सत्यापित खतौनी, फोटो पहचान प्रमाण और आधार कार्ड के आधार पर की जाएगी।
- मंत्रिमंडल ने प्रदेश में प्राकृतिक खेती का प्रसार बढ़ाने एवं सतत् मार्गदर्शन हेतु 'उत्तर प्रदेश प्राकृतिक कृषि बोर्ड' के गठन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की।
- मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश प्राकृतिक कृषि बोर्ड के शासी निकाय के अध्यक्ष होंगे, जबकि कृषि और शिक्षा मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। वित्त, कृषि विपणन, बागवानी और खाद्य-प्रसंस्करण, पशुपालन और दुग्ध विकास, पंचायती राज और ग्रामीण इंजीनियरिंग, सहकारिता, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री शासी निकाय के सदस्य होंगे।
- मुख्य सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त और पशुधन और दुग्ध विकास, बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण, कृषि शिक्षा, कृषि विपणन, पंचायती राज और ग्रामीण विकास, सहकारिता और योजना विभागों के प्रमुख सचिव या अतिरिक्त मुख्य सचिव सदस्य होंगे।

जीआई महोत्सव का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

16 अक्टूबर, 2022 को केंद्रीय संस्कृति एवं संसदीय कार्य राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की ओर से आयोजित छहदिवसीय जीआई महोत्सव का उत्तर प्रदेश के वाराणसी के बड़ा लालपुर स्थित दीनदयाल हस्तकला संकुल में शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- छहदिवसीय जीआई महोत्सव में प्रदर्शनी में 11 राज्यों के जीआई उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई है तथा जीआई मान्यताप्राप्त उत्पादों के 100 स्टॉल लगाए गए हैं।
- केंद्रीय संस्कृति एवं संसदीय कार्य राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि जीआई महोत्सव का उद्देश्य लोकल उत्पादों को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना है। जीआई उत्पाद मानव केंद्रित विकास का अद्भुत नमूना है तथा भारत को विकसित देश बनाने के लिये मानव केंद्रित विकास होना चाहिये।
- ज्ञातव्य है कि शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) में काशी को सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है।
- पद्मश्री रजनीकांत ने बताया कि जीआई उत्पादों का पंजीकरण किया जा चुका है। बनारस की ठंडई को जीआई के 1000वें उत्पाद के रूप में पंजीकृत कराया जाएगा।
- जीआई उत्सव में गोरखपुर का टेराकोटा, गाज़ीपुर की वॉल हैंगिंग, चंदौली का काला चावल, बनारस की तिरंगा बर्फी, ग्लास बिड्स, बनारसी जरदोजी व वुडेन से लेकर वेयर एंड ट्वॉय, सिद्धार्थ नगर का काला नमक चावल, कन्नौज का इत्र, गया का स्टोन क्राफ्ट, भागलपुर की साड़ियाँ, फिरोज़ाबाद का ग्लास मोजैक, फर्रुखाबाद के प्रिंट दुपट्टे का स्टॉल लगाया गया है।
- महोबा का देसावरी व बिहार का मगही पान, मधुबनी की पेंटिंग, राजस्थान की सोजत मेहँदी, कश्मीर की पश्मीना शॉल, झारखंड की कोहबर चित्रकला भी आकर्षण का केंद्र रहे।

लखनऊ, गाज़ियाबाद, प्रयागराज में कूड़े से बनेगी सीएनजी

चर्चा में क्यों ?

17 अक्टूबर, 2022 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने बताया कि इंदौर की तर्ज़ पर प्रदेश के तीन शहरों- लखनऊ, गाज़ियाबाद, प्रयागराज में कूड़े से सीएनजी निर्माण के प्लांट लगाए जाने के आदेश जारी कर दिये गए हैं।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि इंदौर की तर्ज़ पर उत्तर प्रदेश के भी 4 शहरों में गीले कचरे से सीएनजी बनाने की तैयारी है। कूड़े से सीएनजी बनाए जाने की मंज़ूरी के बाद लखनऊ, गाज़ियाबाद, प्रयागराज में पीपीपी मॉडल पर सीएनजी प्लांट लगाए जाएंगे, जबकि गोरखपुर भी कतार में है।
- इनमें रोज़ाना 34000 किलो सीएनजी बनेगी तथा इसे बनाने में रोज़ाना करीब 1000 टन कचरा इस्तेमाल होगा। इससे 3.65 लाख मीट्रिक टन कचरा कूड़ा निस्तारण प्लांट में जाने से बचेगा।
- लखनऊ और गाज़ियाबाद में एक ही कंपनी एवर इनवायरो रिसोर्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कूड़े से सीएनजी बनाएगी, जबकि प्रयागराज में इंडो इनवायरो इंटीग्रेटेड सोल्यूशन लिमिटेड कंपनी को ज़िम्मेदारी दी गई है। इन कंपनियों को खुद अपने खर्चे पर प्लांट लगाना होगा। नगर निगम की तरफ से इन्हें कोई भी आर्थिक मदद नहीं दी जाएगी।
- लखनऊ तथा गाज़ियाबाद नगर निगम कंपनी को एक रुपए की लीज़ पर 12-12 एकड़ ज़मीन देंगे, जबकि प्रयागराज और गोरखपुर नगर निगम को 10-10 एकड़ ज़मीन देना होगा। इस ज़मीन के बदले नगर निगम को रॉयल्टी भी मिलेगी। सीएनजी बनाने वाली कंपनी लखनऊ और गाज़ियाबाद को प्रतिवर्ष 74-74 लाख तथा प्रयागराज और गोरखपुर नगर निगम को 56-56 लाख रुपए रॉयल्टी देगी।
- कूड़े से सीएनजी बनाने का प्लांट लगने के बाद इन चारों शहरों में रोज़ाना 2.50 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड तथा ग्रीनहाउस गैसेज़ कम होंगी।
- लखनऊ तथा गाज़ियाबाद के लिये सीएनजी बनाने में 300-300 टन गीले कचरे का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि प्रयागराज और गोरखपुर के प्लांट में 200-200 टन कचरा रोज़ाना इस्तेमाल होगा। इस तरह चारों शहरों में रोज़ाना 1000 टन कचरे से 34000 किलो सीएनजी बनेगी।
- शासन की कमेटी ऑफ सेक्रेट्रीज ने बताया कि जिन स्थानों पर सीएनजी प्लांट लगाए जाएंगे, वहाँ आने-जाने का रास्ता नगर निगमों को बनाना होगा तथा इसके साथ ही बिजली, पानी, मार्ग प्रकाश व्यवस्था, जल निकासी तथा सीवर की सुविधा भी नगर निगम को देनी होगी, जिससे प्लांटों में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से 8000 लोगों को रोज़गार भी मिलेगा।
- सीएनजी प्लांट से जो जैविक खाद उत्पन्न होगी, उसे किसानों को दिया जाएगा, जिसे गंगा व राज्य की अन्य नदियों के किनारे खेती के लिये इस्तेमाल किया जाएगा। इससे रासायनिक खाद का प्रयोग कम होगा और मिट्टी की उर्वराशक्ति बढ़ेगी। साथ ही नदी के पानी में रासायनिक उर्वरकों का मिश्रण भी रुकेगा।

उत्तर प्रदेश ने कपड़ा और परिधान नीति की घोषणा की

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने नए निवेश को आकर्षित करने और उत्तर प्रदेश को कपड़ा एवं परिधान उद्योग का केंद्र बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश कपड़ा और परिधान नीति की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि 13 अक्टूबर, 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तर प्रदेश कपड़ा और परिधान नीति को मंज़ूरी दी गई थी।
- नीति की घोषणा करते हुए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री राकेश सचान ने कहा कि यह नीति रोज़गार प्रधान है और इसका उद्देश्य 10,000 करोड़ रुपए के नए निवेश को आकर्षित करना तथा 5 लाख से अधिक नई नौकरियाँ पैदा करना है।
- नई नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य को वैश्विक स्तर के परिधान निर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना और कपड़ा उद्योग से संबंधित सभी प्रकार की इकाइयों, जैसे- हथकरघा, पावरलूम, कताई, बुनाई, प्रसंस्करण और परिधान का सतत् विकास करना है।

नोट :

- मंत्री राकेश सचान ने कहा कि कपड़ा और वस्त्र नीति सभी हितधारकों से परामर्श करने और उनकी चिंताओं का ध्यान रखने के बाद तैयार की गई है। नीति को निवेशक अनुकूल बनाने के लिये कई प्रक्रियाओं को ऑनलाइन किया गया है और निवेशकों की सुविधा के लिये एक हेल्प डेस्क बनाई गई है।

उत्तर प्रदेश में 15 सीएचसी पीपीपी मोड पर चलेंगे

चर्चा में क्यों?

18 अक्टूबर, 2022 को उत्तर प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, जिनके पास स्वास्थ्य विभाग का प्रभार भी है, ने बताया कि राज्य सरकार लखनऊ सहित ज़िलों के 15 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के आधार पर चलाएगी।

प्रमुख बिंदु

- उप-मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि सीएचसी में 24 घंटे की आपातकालीन सेवा, मुफ्त प्रवेश, दवा और नैदानिक सेवाएँ होंगी।
- चयनित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में लखनऊ का नगरम, वाराणसी का गजोखर, कुशीनगर का खडन्न, गोरखपुर का बेलाघाट, चित्रकूट का राजापुर, श्रावस्ती का मल्हीपुर, लखीमपुर खीरी का चंदन चौकी, बहराइच का विश्वरगंज, चंदौली का भोगवाड़ा, महराजगंज का अडन्न बाज़ार, बलिया का सुखपुरा, फतेहपुर में दपसौरा, सोनभद्र में बभानी, बलरामपुर में खजुरिया और सिद्धार्थ नगर में सिरसिया शामिल हैं।
- उप-मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि यह प्रयोग सीएचसी में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम होगा और आवश्यकता के अनुसार नवीनतम चिकित्सा उपकरण वहाँ स्थापित किये जाएंगे।

अब उत्तर प्रदेश में भी मेडिकल की पढ़ाई होगी हिन्दी में

चर्चा में क्यों?

19 अक्टूबर, 2022 को उत्तर प्रदेश की चिकित्सा शिक्षा महानिदेशक श्रुति सिंह ने बताया कि मध्य प्रदेश की तर्ज़ पर अब राज्य के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस पाठ्यक्रमों के लिये हिन्दी भाषा की पाठ्य-पुस्तक पेश करने हेतु सरकार ने एक तीन सदस्यीय पैनल का गठन किया है।

प्रमुख बिंदु

- महानिदेशक श्रुति सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने जिस तीन सदस्यीय पैनल का गठन किया है, वह तीन विषयों पर एमबीबीएस हिन्दी पाठ्य-पुस्तकों की समीक्षा कर रहा है। इनमें जैव रसायन, शरीर रचना और चिकित्सा शरीर विज्ञान शामिल हैं।
- इसके अलावा अन्य एमबीबीएस पाठ्य-पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद किया जा रहा है और तीन सदस्यीय पैनल समिति इस अनुवाद की जाँच करेगी।
- गौरतलब है कि हाल ही में देश में पहली बार मध्य प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई हिन्दी में शुरू की गई है।
- चिकित्सा शिक्षा महानिदेशक ने कहा कि लगभग एक महीने पहले समिति का गठन किया गया था और मेरठ स्थित एक सरकारी मेडिकल कॉलेज से इन पुस्तकों को पहले अपनाने की उम्मीद है। अभी हिन्दी की पाठ्य-पुस्तकें केवल एमबीबीएस छात्रों तक ही सीमित रहेंगी।
- उन्होंने कहा कि इस कदम से छात्रों, विशेष रूप से हिन्दी-माध्यम पृष्ठभूमि वाले छात्रों को अपनी भाषा में अवधारणाओं और प्रक्रियाओं को आसानी से समझने में मदद मिलेगी।
- चिकित्सा शिक्षा के अतिरिक्त निदेशक एनसी प्रजापति ने कहा कि पैनल चिकित्सा शब्दावली का अनुवाद और पाठ्य-पुस्तकें हटाने की कोशिश नहीं कर रहा है। संपूर्ण पाठ का अनुवाद करना संभव नहीं है, क्योंकि यह छात्रों के लिये जटिल साबित होगा।

उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति-2022

चर्चा में क्यों ?

20 अक्टूबर, 2022 को उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव दुग्ध विकास विभाग डॉ. रजनीश दुबे ने उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति-2022 की अधिसूचना जारी कर दी।

प्रमुख बिंदु

- डॉ. रजनीश दुबे ने बताया कि इस नीति का उद्देश्य दुग्ध प्रसंस्करण के स्तर को 10 से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करना और बाज़ार के लिये उपलब्ध दूध को 44 से बढ़ाकर 65 फीसदी करना है तथा इसके द्वारा दुग्ध उत्पाद जैसे चीज, आइसक्रीम इत्यादि का विनिर्माण करने वाली नवीन इकाई की स्थापना के लिये लाभान्वित किया जाएगा। यह नीति पाँच सालों के लिये प्रभावी होगी।
- इस नीति में कोल्ड चेन की स्थापना के लिये दुग्ध केंद्र के उपकरण, बल्क मिल्क कूलर, रेफ्रिजरेटेड वैन, कूलिंग वैन, रोड मिल्क टैंकर, आइसक्रीम ट्रॉली आदि खरीद पर भी मिलेगी।
- उन्होंने बताया कि राज्य के सभी जिलों में दुग्ध प्रसंस्करण व दुग्ध उत्पाद विनिर्माण दुग्धशाला इकाइयों की स्थापना या विस्तारीकरण में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि के लिये संयंत्र, तकनीकी सिविल कार्य व स्पेयर पार्ट्स की लागत का 10 प्रतिशत, अधिकतम पाँच करोड़ रुपए तक तथा प्लांट मशीनरी, तकनीकी सिविल कार्य और स्पेयर पार्ट्स का ऋण पर देय ब्याज की दर के पाँच प्रतिशत अधिकतम 1000 करोड़ रुपए दिया जाएगा। इसमें नए पशु आहार व पशु पोषण उत्पाद इकाई के लिये प्लांट लगाने को पाँच वर्षों के लिये अधिकतम 7.50 करोड़ रुपए दिया जाएगा।
- इस नीति में तकनीकी कामों के लिये 2.50 करोड़ व क्वालिटी कंट्रोल उपकरण, जैसे ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट (कोल्ड चेन के अतिरिक्त) के लिये एक करोड़ दिया जाएगा।
- कोल्ड चेन की स्थापना के लिये रेफ्रीजरेटेड वैन, इन्सुलेटेड वैन, रोड मिल्क टैंकर, बल्क मिल्क कूलर, आइसक्रीम ट्राली के लिये एक करोड़ दिया जाएगा तथा विस्तारीकरण के लिये 2.50 करोड़ दिया जाएगा।
- पशु आहार व पशु पोषण उत्पाद निर्माणशाला इकाई के विस्तारीकरण के लिये दो करोड़ मिलेगा। सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्र के तहत आने वाली मूल्य संवर्धित दुग्ध उत्पाद जैसे-चीज, आइसक्रीम आदि का विनिर्माण करने वाली इकाइयों का प्लांट लगाने के लिये दो करोड़ दिया जाएगा। नई इकाइयों के लगने की 10 साल की अवधि में भुगतान, विद्युत शुल्क की प्रतिपूर्ति दी जाएगी। स्टांप शुल्क नीति के अंतर्गत छूट दी जाएगी।
- राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि राज्य सरकार उत्तर प्रदेश के दूध उत्पादों की ब्रांडिंग के लिये हर साल 20 लाख रुपए तीन सालों तक देगी एवं निर्यात प्रोत्साहन के लिये यह राशि 40 लाख रुपए होगी तथा अन्य देशों में उत्पाद का नमूना भेजने के लिये कुल लागत का 50 प्रतिशत दिया जाएगा। इसके अलावा उत्पादों के मानकीकरण के लिये पाँच लाख रुपए का अनुदान भी दिया जाएगा।

उत्तर मध्य रेलवे हुआ शत-प्रतिशत विद्युतीकरण वाला देश का पाँचवा ज़ोन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर) शत-प्रतिशत विद्युतीकरण वाला देश का पाँचवा ज़ोन बन गया है। यहाँ के सभी ब्रॉड गेज रेलमार्ग का अब पूर्णरूप से विद्युतीकरण हो गया है।

प्रमुख बिंदु

- वर्तमान में देश के 18 ज़ोनल रेलवे में अभी चार ज़ोन पूर्व तटीय रेलवे भुवनेश्वर, पूर्व रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे तथा दक्षिण-पूर्व रेलवे ही ऐसे ज़ोन थे, जो पूर्णरूप से विद्युतीकृत थे। अब इसमें उत्तर मध्य रेलवे भी शामिल हो गया है।
- इस रेलखंड में खजुराहो से ललितपुर के बीच ईशानगर-उदयपुर के बीच 76 किमी. विद्युतीकरण का कार्य बीते वित्तीय वर्ष में रह गया था, जिसे केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन (कोर) द्वारा 20 अक्टूबर को पूरा कर लिया गया है। अब यह रूट इलेक्ट्रिक इंजन लगी ट्रेनों के संचालन के लिये तैयार हो गया है।

नोट :

- अब इस रेलखंड का विद्युतीकरण होने के साथ ही एनसीआर के ब्रॉड गेज वाले सभी रेलमार्ग का विद्युतीकरण हो गया है। इसका लाभ यह होगा कि अब महोबा-खजुराहो-उदयपुरा होते हुए ललितपुर तक इलेक्ट्रिक इंजन लगी ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा। साथ ही, महोबा से छतरपुर होते हुए ललितपुर तक मेमू ट्रेनें चल सकेंगी।
- ईशानगर-उदयपुरा रेलखंड के विद्युतीकरण के साथ ही उत्तर मध्य रेलवे ज़ोन में 3222 रूट किमी. ब्रॉड गेज का विद्युतीकरण हो गया है। इस नए रूट पर 110 किमी. प्रतिघंटे की रफ्तार से ट्रेनें चल सकेंगी, यानी प्रयागराज से महोबा होते हुए ललितपुर तक 110 किमी/घंटा की रफ्तार से ट्रेन चल सकेगी। इससे यात्रियों के समय की भी बचत होगी।
- गौरतलब है कि उत्तर मध्य रेलवे अपने वर्तमान स्वरूप में 1 अप्रैल, 2003 को अस्तित्व में आया था। उत्तर मध्य रेलवे भारत के विस्तृत क्षेत्रों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान व हरियाणा में फैला हुआ है। इसका मुख्यालय प्रयागराज (इलाहाबाद) में है और इसमें तीन मंडल- प्रयागराज, झाँसी एवं आगरा शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश के सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक में मेडिक्लेम से मिलेगा कैशलेस इलाज

चर्चा में क्यों ?

24 अक्तूबर, 2022 को उत्तर प्रदेश के जीएसवीएम सुपर स्पेशियलिटी पीजीआई के नोडल अधिकारी डॉ. मनीष सिंह ने बताया कि राज्य में अब जीएसवीएम पीजीआई समेत 6 मेडिकल कॉलेजों में बनाए गए सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉकों में मेडिक्लेम से मरीजों को कैशलेस इलाज मिलेगा। इसके लिये राज्य शासन ने भी स्वीकृति प्रदान कर दी है।

प्रमुख बिंदु

- नोडल अधिकारी डॉ. मनीष सिंह ने बताया कि सुपर स्पेशियलेटी ब्लॉकों को मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के मॉडल पर चलाया जाएगा। इसके लिये मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के ब्लू प्रिंट का अध्ययन भी किया जा रहा है।
- सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉकों में मेडीक्लेम के मरीजों का इलाज करने के लिये टीपीए ब्लॉक भी बनाया जाएगा, ताकि मरीजों को मेडिक्लेम के लिये दौड़भाग न करनी पड़े।
- ज्ञातव्य है कि सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत बनाया गया है।
- राज्य में 6 मेडिकल कॉलेज कानपुर, आगरा, मेरठ, प्रयागराज, झाँसी गोरखपुर में बनाए गए है। जीएसवीएम सुपर स्पेशियलिटी जीपीआई मेरठ, कानपुर और गोरखपुर में बनकर तैयार हो गया है और यहाँ पर मरीजों का सुपर स्पेशियलिटी इलाज भी शुरू हो चुका है।
- डॉ. मनीष सिंह ने बताया कि राज्य में अभी तक सब कुछ मेडिकल कॉलेजों के संसाधनों से संचालित किया जा रहा है। लेकिन आने वाले एक महीने में इन्हें सोसाइटी बनाकर चलाया जाएगा।
- विदित है कि राज्य में अभी तक इन मेडिकल कॉलेजों को केजीएमयू-एसजीपीजीआई के मॉडल पर चलाने की तैयारी की जा रही थी, परंतु अब इन्हें राज्य शासन द्वारा मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज मॉडल पर चलाया जाएगा।
- जीएसवीएम पीजीआई में न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रो, नेप्रो की ओपीडी लगनी शुरू हो गई है तथा कुछ ही दिनों में यहाँ गैस्ट्रो सर्जरी, यूरो की भी ओपीडी और इनडोर को शुरू किया जाएगा।
- आने वाले पाँच सालों के लिये पीजीआई के मेंटीनेस का काम निर्माण एजेंसी हाइड्स को सौंपा गया है।

तराई हाथी अभयारण्य को केंद्र की मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

23 अक्तूबर, 2022 को उत्तर प्रदेश वन विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय ने तराई हाथी रिज़र्व (टीईआर) को अपनी मंज़ूरी दे दी है, जिसे दुधवा टाइगर रिज़र्व और लखीमपुर एवं पीलीभीत ज़िलों में स्थित पीलीभीत टाइगर रिज़र्व सहित 3,049 वर्ग किमी. क्षेत्र में विकसित किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- उत्तर प्रदेश वन विभाग के अनुसार, विभाग ने अप्रैल में प्रस्ताव तैयार किया था और इसे 11 अक्तूबर को केंद्र को भेज दिया था। टीईआर के लिये केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय से मंज़ूरी मिलने के बाद अब जल्द ही राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की जाएगी।
- गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में तराई हाथी रिज़र्व के अस्तित्व में आने के साथ, दुधवा टाइगर रिज़र्व उत्तर प्रदेश में अकेला राष्ट्रीय उद्यान होगा जो चार प्रतिष्ठित जंगली जानवरों की प्रजातियों - बाघ, एक सींग वाला गैंडा, एशियाई हाथी और दलदली हिरण की रक्षा और संरक्षण करेगा।
- दुधवा और पीलीभीत टाइगर रिज़र्व के अलावा, हाथी रिज़र्व में किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य, कतर्नियाघाट वन्यजीव अभयारण्य, दुधवा बफर ज़ोन और दक्षिण खीरी वन प्रभाग के कुछ हिस्से शामिल होंगे।
- तराई हाथी अभयारण्य की स्थापना वन्यजीव संरक्षण के मामले में एक मील का पत्थर होगी, विशेष रूप से एशियाई हाथियों के लिये, क्योंकि यह भारत-नेपाल सीमा पर स्थित है, जहाँ हाथियों की सीमा-पार आवाजाही एक नियमित दिनचर्या है।
- केंद्र हाथी परियोजना के तहत सभी वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करेगा, जो मानव-हाथी संघर्षों को सँभालने में मदद करेगा। दुधवा में हाथी अभयारण्य की स्थापना से उनके संरक्षण के प्रति हाथी केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने में मदद मिलेगी।
- साथ ही, परियोजना हाथी के तहत प्राप्त वित्तीय और तकनीकी सहायता का उपयोग दुधवा के शिविर में मौजूद हाथियों के प्रबंधन में किया जाएगा और मानव-हाथी संघर्ष की घटनाओं, जो वर्तमान में राज्य पर निर्भर हैं, को अधिक प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि दुधवा टाइगर रिज़र्व ने दशकों से विभिन्न घरेलू और सीमा पार गलियारों के माध्यम से जंगली हाथियों को आकर्षित किया है, जिसमें बसंता-दुधवा, लालझड़ी (नेपाल) -सथियाना और शुक्लाफांटा (नेपाल)-ढाका-पीलीभीत-दुधवा बफर ज़ोन कॉरिडोर शामिल हैं। प्रोजेक्ट एलीफेंट के तहत तराई एलीफेंट रिज़र्व इन गलियारों को पुनर्जीवित करने या बहाल करने में मदद करेगा, जो खराब हो गए हैं।

नोएडा एयरपोर्ट पर देश के सबसे बड़े मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और ओवरहालिंग (एमआरओ) के निर्माण का रास्ता साफ

चर्चा में क्यों ?

25 अक्तूबर, 2022 को जेवर में बन रहे क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया के चौथे सबसे बड़े एयरपोर्ट के दूसरे चरण के निर्माण के लिये मार्ग पूरी तरह से प्रशस्त हो गया है। इससे नोएडा एयरपोर्ट पर देश के सबसे बड़े मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और ओवरहालिंग (एमआरओ) के निर्माण का रास्ता भी साफ हो गया है।

प्रमुख बिंदु

- पहले चरण के निर्माण लिये 1334 हेक्टेयर भूमि पूर्व में अधिग्रहण हो चुका है। इस पर निर्माण कार्य शुरू है। दूसरे चरण के निर्माण के लिये भूमि न मिलने की बाधा थी, पर उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों से छह गाँवों के किसान अपनी 1365 हेक्टेयर भूमि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (नियाल) को देने को तैयार हो गए हैं।
- नए भूमि अधिग्रहण कानून के हिसाब से किसी भी परियोजना के लिये भूमि अधिग्रहण हेतु प्रभावित होने वाले 70 प्रतिशत किसानों की सहमति ज़रूरी है। 7164 किसानों में से करीब 80 प्रतिशत ने अपनी मंज़ूरी दे दी है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि. (नियाल) के पास अब 2699 हेक्टेयर भूमि हो जाएगी।
- एयरपोर्ट के लिये कुल 6200 हेक्टेयर भूमि आरक्षित है। क्षेत्रफल के मामले में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। इससे पहले किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट सऊदी अरब, डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट व डलास इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमेरिका आदि तीन एयरपोर्ट ही क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़े हवाई अड्डों में शुमार थे। हालाँकि, रनवे के मामले में दूसरे अन्य एयरपोर्ट बड़े हैं। यहाँ कुल पाँच रनवे बनने हैं।
- उल्लेखनीय है कि जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण अलग-अलग चरणों में पूरा होगा। पहले चरण के लिये 1334 हेक्टेयर भूमि पर दो रनवे का निर्माण कार्य शुरू है। पहले फेज का निर्माण भी चार भागों में होगा। एक रनवे का निर्माण कार्य 2024 में पूरा हो जाएगा। इस पर करीब 5700 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

- एयरपोर्ट के चालू होने पर शुरुआती दौर में सालाना एक करोड़ 20 लाख यात्री सफर करेंगे। संख्या बढ़ने पर दूसरे चरण में एक और रनवे का निर्माण होगा। बाकी दो और रनवे का निर्माण अगले चरणों में होगा। चारों चरण पूरे होने पर एयरपोर्ट से सालाना करीब सात करोड़ यात्री सफर करेंगे।
- इस परियोजना पर कुल 30 हज़ार करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। एयरपोर्ट के निर्माण के लिये दूसरे चरण में जिस भूमि को लिया जा रहा है, उस पर एक रनवे व एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और ओवरहालिंग (एमआरओ) का केंद्र बनेगा।
- विदित है कि देश के 85 प्रतिशत हवाई जहाज़ मेंटेनेंस रिपेयर, ओवरहालिंग के लिये विदेश जाते हैं। इस पर सालाना 15 हज़ार करोड़ रुपए खर्च होते हैं। यह रकम विदेश चली जाती है। नोएडा एयरपोर्ट एमआरओ का बड़ा केंद्र बनने से विदेश जाने वाली मुद्रा की बचत होगी और युवाओं को रोज़गार भी मिलेगा।

लंपी वायरस के टीकाकरण में उत्तर प्रदेश देश में अव्वल

चर्चा में क्यों?

26 अक्टूबर, 2022 को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि पशुओं में लंपी वायरस की रोकथाम के लिये सरकारी अभियान में 1.50 करोड़ पशुओं का टीकाकरण करके उत्तर प्रदेश ने देश में पहला स्थान हासिल किया है। प्रदेश में लंपी वायरस से रिकवरी दर 95 प्रतिशत है।

प्रमुख बिंदु

- प्रवक्ता ने बताया कि उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर गुजरात रहा। मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश के 32 ज़िले लंपी वायरस से प्रभावित हैं। इनमें करीब 1.05 लाख पशु लंपी वायरस से ग्रस्त हैं।
- यह उपलब्धि मात्र दो महीने के अभियान में प्राप्त हुई है। कोरोना की तर्ज़ पर पशुओं में तेज़ी से फैल रहे लंपी जैसे घातक रोग को नियंत्रित करने के लिये अभियान की शुरुआत की गई थी।
- इसके मद्देनज़र घर-घर पशु चिकित्सकों को भेजकर उपचार किया गया, जिससे अब तक 1 लाख से अधिक पशु रोगमुक्त हो चुके हैं। विभाग द्वारा टीम-9 का गठन किया गया, जिसके वरिष्ठ नोडल अधिकारियों द्वारा प्रभावित बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, आगरा और अलीगढ़ मंडलों में अभियान चलाकर लंपी चक्र को तोड़ा गया।
- प्रवक्ता ने बताया कि चिकित्सकों की टीम द्वारा 26 ज़िलों में 89 डेडीकेटेड गो चिकित्सा स्थल बनाकर भी संक्रमण के फैलाव को रोका गया। 1.50 करोड़ टीकाकरण लक्ष्य लगभग 2000 टीमों द्वारा पूरा किया गया है, जबकि 31 अक्टूबर तक 1.60 करोड़ पशुओं के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है।
- गौरतलब है कि लंपी स्किन डिजीज को 'गांठदार त्वचा रोग वायरस' भी कहा जाता है। वहीं शार्ट में LSDV कहा जाता है। यह एक संक्रामक बीमारी है, जो एक पशु से दूसरे पशु को होती है। आसान शब्दों में कहें तो संक्रमित पशु के संपर्क में आने से दूसरा पशु भी बीमार हो सकता है।
- यह बीमारी Capri Pox अपतने नामक वायरस के चलते होती है। इस वायरस का संबंध गोट फॉक्स और शीप पॉक्स वायरस के फैमिली से है। जानकारों की मानें तो मच्छर के काटने और खून चूसने वाले कीड़ों के ज़रिये यह बीमारी मवेशियों को होती है।
- विदित है कि इस वायरस की चपेट में आने से अब तक हज़ारों मवेशी काल के गाल में समा गए हैं। सरकारी रिपोर्ट की मानें तो 50 हज़ार से अधिक गायों और भैंसों की मौत हो चुकी है। वहीं, लाखों की संख्या में मवेशी लंपी वायरस की चपेट में है। राजस्थान में लंपी वायरस का कहर अधिक देखने को मिल रहा है। अब तक लंपी वायरस का एंटीडोज तैयार नहीं हुआ है, इस वजह से बड़ी संख्या में मवेशियों की मौत हुई है।

नोट :

उत्तर प्रदेश पुलिस होगी अब हाईटेक

चर्चा में क्यों ?

27 अक्टूबर, 2022 को मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 650 करोड़ से अधिक की धनराशि खर्च कर अब उत्तर प्रदेश पुलिस को हाईटेक किया जा एगा।

प्रमुख बिंदु

- उत्तर प्रदेश पुलिस को हाईटेक करने की दिशा में जल्द ही इसे बॉडी वार्न कैमरा और फुल बॉडी प्रोटेक्टर से लैस किया जाएगा।
- गृह विभाग ने पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत 1200 बॉडी वार्न कैमरा खरीदने के लिये 4.8 करोड़ रुपए और 1650 फुल बॉडी प्रोटेक्टर फॉर वीमेन की खरीद के लिये 2.48 करोड़ रुपए तथा 30 हज़ार पोस्टमार्टम किट खरीदने के लिये छह करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है
- प्रदेश के 10 ज़िलों में करीब 641 करोड़ रुपए खर्च कर उच्चीकृत सोशल मीडिया मॉनीटरिंग सेल की स्थापना होने वाली है। इसी तरह 10 अन्य ज़िलों में लॉ एंड ऑर्डर के लिये क्यूआरटी की स्थापना की जाएगी।
- इसके अलावा 75 करोड़ रुपए की लागत से एसआईटी, ईओडब्ल्यू, सीबीसीआईडी और एसीओ के जाँच और विवेचना के लिये एक डेडिकेटेड एफएसएल की स्थापना की जाएगी। कन्नौज में डेडिकेटेट मिनी टेक्निकल लैब विकसित की जा रही है।
- एनसीआरबी की ओर से विकसित क्राइम सीन वीडियोग्राफी ऐप को पहले चरण में मुज़फ्फरनगर, बाराबंकी और अलीगढ़ में शुरू किया गया है तथा प्रदेश के अन्य ज़िलों में भी इसे लागू करने के लिये कार्य योजना तैयार की गई है। इसके लिये तकनीकी सेवा मुख्यालय ने पूरी प्रक्रिया हेतु तकनीकी समिति गठित की है।
- विदित है कि प्रदेश के सभी 1531 थानों में साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना हो चुकी है। प्रदेश के सभी 18 परिक्षेत्रीय साइबर थानों के प्रशासनिक भवन निर्माण संबंधी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है तथा सात परिक्षेत्रीय साइबर थानों वाराणसी, झाँसी, बस्ती, अलीगढ़, आज़मगढ़, गोरखपुर और बाँदा के लिये कार्यदायी संस्था नामित कर दी गई है।

प्लास्टिक कचरा उत्सर्जन में उत्तर प्रदेश आठवें स्थान पर

चर्चा में क्यों ?

27 अक्टूबर, 2022 को जारी प्लास्टिक अल्टरनेटिव रिपोर्ट-2022 के अनुसार देश में प्लास्टिक कचरा उत्सर्जन के मामले में उत्तर प्रदेश आठवें स्थान पर है।

प्रमुख बिंदु

- रिपोर्ट में विभिन्न राज्यों द्वारा कचरे को रिसाइकिल कर पुन: इस्तेमाल के लिये नवप्रयोगों के बारे मंक भी बताया गया है।
- विदित है कि उत्तर प्रदेश ने 2018 से सिंगल यूज़ प्लास्टिक के निर्माण, संग्रह, परिवहन, बिक्री, रिसाइकिलिंग के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा रखा है तथा प्रदेश में प्लास्टिक कचरे को ईंधन में बदलने के दो प्लांट लगाए गए हैं।
- राज्य के प्रयागराज में इसी तरह का एक प्लांट पिछले साल ही लगाया गया है। इसमें सिंगज यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल कर उसे ईंधन में बदला जाता है। इसके अलावा एक प्लांट मथुरा में पहले से ही काम कर रहा है। इन दोनों प्लांट की क्षमता 2700 टन प्रति साल है।
- प्लांट लगाने के अलावा प्लास्टिक कचरे का इस्तेमाल सड़क निर्माण में भी हो रहा है तथा पेपर मिलों ने सीमेंट मिल के साथ इस तरह के कचरे को नए रूप में इस्तेमाल करने की पहल की है।
- प्लास्टिक अल्टरनेटिव रिपोर्ट-2022 में बताया गया है कि देश में प्लास्टिक कचरा उत्सर्जन के मामले में महाराष्ट्र का अव्वल स्थान है तथा प्रति व्यक्ति कचरा निकालने के मामले में गोवा नंबर एक पर है। इसके बाद दिल्ली व केरल का स्थान है और उत्तर प्रदेश 28वें नंबर पर है। सबसे कम प्रति प्रति व्यक्ति प्लास्टिक कचरा उत्सर्जन के मामले में नागालैंड, सिक्किम व त्रिपुरा शीर्ष पर हैं।

नोट :

प्लास्टिक कचरा उत्सर्जन में अन्य राज्यों की स्थिति-

राज्य	प्लास्टिक कचरा उत्सर्जन (प्रतिशत में)
महाराष्ट्र	13
तमिलनाडु	12
गुजरात	12
पश्चिम बंगाल	9
कर्नाटक	9
तेलंगाना	7
दिल्ली	7
उत्तर प्रदेश	5
हरियाणा	4
केरल	4
मध्य प्रदेश	3
पंजाब	3
अन्य	11

- इस रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में हर साल 34,69,780 टन प्लास्टिक कचरा निकलता है। यह आँकड़ा साल 2019-20 का है। देश में प्रति व्यक्ति प्लास्टिक कचरा उत्सर्जन पाँच सालों यानी 2016-20 में दोगुना हो गया।
- रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि स्वच्छ भारत मिशन के चलते देश के विभिन्न राज्यों में कचर प्रबंधन इंफ्रास्ट्रचर काफी मज़बूत हुआ है और अब प्लास्टिक कचरे को दूसरे रूपों में तब्दील कर अन्यत्र उसका इस्तेमाल करने का चलन नई तकनीक के साथ बढ़ा है। हालाँकि, इसे और व्यापक स्तर पर ले जाने की ज़रूरत है, क्योंकि यह अभी पर्याप्त नहीं है।

लखनऊ में एशिया की पहली पैथोजेन रिडक्शन मशीन का लोकार्पण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू) में थोरेसिक सर्जरी और वेस्कुलर सर्जरी विभाग के साथ ट्रांसफ्यूज़न मेडिसिन विभाग में एशिया की पहली पैथोजेन रिडक्शन मशीन का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि रक्त की अनेक अशुद्धियाँ ऐसी होती हैं, जो अधिसंख्य जाँचों में पकड़ में नहीं आती हैं और इस अशुद्ध रक्त के किसी मरीज़ को चढ़ाए जाने पर उसे सेप्सिस जैसे संक्रमण हो सकते हैं।
- इस संक्रमण से बचाव हेतु एशिया की पहली पैथोजेन मशीन शुरू की गई है, जो केवल 15 मिनट में 4 यूनिट रक्त की अशुद्धियों को दूर कर सकती है।
- इस मशीन से प्लेटलेट्स और प्लाज्मा में शुरुआती दौर में हुए किसी भी प्रकार के संक्रमण को समाप्त किया जा सकता है, जो अंग प्रत्यारोपण अथवा कमज़ोर इम्यूनिटी वाले मरीज़ों के लिये बेहद लाभदायक साबित होगी।
- डेंगू, स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया, साइटोमैगिलो वायरस समेत लगभग 200 ऐसे बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ आदि रक्तदाता के रक्त में रह सकते हैं और रक्तग्राही के रक्त में जाकर संक्रमण पैला सकते हैं। यह मशीन इन्हीं संक्रमण को समाप्त कर सकती है।
- केजीएमयू के ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग की अध्यक्ष डॉ. तूलिका चंद्रा के अनुसार पेथोजेन की किट में चार अलग-अलग ब्लड यूनिट को रखा जाता है, जो रक्त यूनिट में अल्ट्रवायलेट इम्यूमिनेटर के द्वार 10-15 मिनट में ही रक्त के सभी प्रकार के जीवाणु को हटाकर रक्त यूनिट को पूरी तरह शुद्ध करती है।

लखनऊ में होगा इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन

चर्चा में क्यों?

28 अक्टूबर, 2022 को वाराणसी में मलदहिया स्थित विनायक प्लाजा में हुई इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की बैठक में आईआईए की फूड प्रोसेसिंग कमेटी के राष्ट्रीय चेयरमैन दीपक बजाज ने बताया कि इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से 2 से 4 नवंबर तक लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन होगा।

प्रमुख बिंदु

- दीपक बजाज ने बताया कि इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन तीनदिवसीय होगा, जिसमें फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्यमियों को इससे संबंधित जानकारी दी जाएगी तथा इसमें पूर्वांचल समेत उत्तर प्रदेश के 45 शहरों से 100 से अधिक उद्यमी हिस्सा लेंगे।
- फूड प्रोसेसिंग मशीनों तथा फूड प्रोसेसिंग तकनीकी का यह देश का सबसे बड़ा एक्सपो है और इसमें बनारस समेत आसपास के ज़िलों से होटल उद्यमी, रेस्टोरेंट संचालक, बेकरी उत्पादों के निर्माता भाग लेंगे।
- इंडिया फूड एक्सपो में एमएसएमई के तहत ओडीओपी के विभिन्न स्टॉल लगाए जाएंगे तथा देश एवं विदेश के फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, मशीनों पर हुए नए इनोवेशन को भी इसमें शामिल किया गया है।
- इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आरके चौधरी ने इंडिया फूड एक्सपो के संबंध में सरकार को उद्योगों में उपयोग होने वाले विभिन्न लाइसेंस जैसे फायर, प्रदूषण आदि की प्रक्रिया को आसान करने तथा टेक्सटाइल पॉलिसी 2017 की अनुदान राशि अवमुक्त करने को कहा, जिससे उद्योगों का सुगम संचालन हो सके।

गंगा और उसकी सहायक नदियों का कायाकल्प कर रही राज्य सरकार

चर्चा में क्यों?

28 अक्टूबर, 2022 को उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि राज्य सरकार नमामि गंगे कार्यक्रम के दूसरे चरण (2021-2026 की अवधि के लिये) में, सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ाकर गंगा की सहायक नदियों पर उचित सीवरेज बुनियादी ढाँचे के निर्माण में संलग्न है और सर्कुलर वाटर इकॉनमी मॉडल, कीचड़ और सेप्टेज प्रबंधन आदि पर ज़ोर दे रही है।

प्रमुख बिंदु

- जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में गंगा के महत्त्व को बहाल करने और इसके संरक्षण एवं बचाव के लिये विभिन्न पहलों के माध्यम से राज्य में महत्त्वाकांक्षी नमामि गंगे परियोजना को आगे बढ़ाया जा रहा है।
- उन्होंने बताया कि सितंबर 2022 से दिसंबर 2022 तक केवल चार महीनों में राज्य में कुल आठ परियोजनाएँ पूरी की जाएंगी। इन परियोजनाओं में 59 करोड़ रुपए की लागत से प्रयागराज के नैनी, फाफामऊ और झूंसी क्षेत्रों के लिये 72 एमएलडी क्षमता के तीन एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) शामिल हैं।
- इसी प्रकार कानपुर नगर में 23 करोड़ रुपए की लागत से 160 एमएलडी क्षमता के एसटीपी का निर्माण, उन्नाव में 102.2 करोड़ रुपए की लागत से 15 एमएलडी क्षमता के इंटरसेप्शन एवं डायवर्जन स्ट्रक्चर का निर्माण तथा उन्नाव के शुक्लागंज में 65.18 करोड़ रुपए की लागत से 5 एमएलडी क्षमता के इंटरसेप्शन और डायवर्जन स्ट्रक्चर का निर्माण किया जा रहा है।
- इसके अलावा, सुल्तानपुर में 18 करोड़ रुपए की लागत से 17 एमएलडी क्षमता के इंटरसेप्शन और डायवर्सन संरचनाएँ, बुढाना में 48.76 करोड़ रुपए की लागत से 10 एमएलडी क्षमता और जौनपुर में 206 करोड़ रुपए की लागत से 30 एमएलडी क्षमता का निर्माण किया जा रहा है। बागपत में 77.36 करोड़ रुपए की लागत से 14 एमएलडी क्षमता इंटरसेप्शन और डायवर्जन स्ट्रक्चर का निर्माण कार्य दिसंबर 2022 तक पूरा हो जाएगा।
- राज्य में अनुमानित सीवेज उत्पादन लगभग 5,500 एमएलडी है, जिसके एक बड़े हिस्से का उपचार राज्य में स्थापित 114 एसटीपी द्वारा किया जाता है, जिसकी कुल क्षमता 3,539.72 एमएलडी है।

नोट :

- इस अंतर को पाटने के लिये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार को कई सीवरेज परियोजनाओं का प्रस्ताव दिया है। परिणामस्वरूप, केंद्र सरकार ने राज्य में 11,433.06 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 1,574.24 एमएलडी क्षमता के एसटीपी के निर्माण के लिये कुल 55 सीवरेज बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को मंज़ूरी दी है।
- विदित है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा आयोजित लगातार समीक्षा बैठकों के माध्यम से निरंतर निगरानी के कारण उत्तर प्रदेश (कन्नौज से वाराणसी) में बहने वाली गंगा में बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड (बीओडी) में सुधार देखा गया है।
- वर्ष 2014 और 2022 के दौरान सभी तुलनीय स्थानों (सभी 20 स्थानों) पर स्नान करने के लिये जल गुणवत्ता मानदंड को पूरा किया गया, जहाँ 20 में से 16 जगहों पर DO (डिसोल्व्ड ऑक्सीजन) में सुधार हुआ है, वहीं 20 में से 14 जगहों पर BOD और 20 में से 18 जगहों पर FC में सुधार हुआ है।
- केंद्र सरकार ने पहले कहा था कि 2014 से पहले प्रयागराज के लिये स्वीकृत कोई भी सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना पूरी नहीं हुई थी। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) द्वारा 42+16+14 एमएलडी क्षमता के तीन एसटीपी को भी मंज़ूरी दी गई थी, ताकि अतिरिक्त अपशिष्ट जल का उपचार किया जा सके।
- एनएमसीजी ने नैनी, सलोरी और राजापुर में मौजूदा एसटीपी को अपग्रेड करने की एक परियोजना को भी मंज़ूरी दी है। प्रयागराज की स्थिति को ध्यान में रखते हुए एनएमसीजी ने इन दोनों परियोजनाओं को हाइब्रिड वार्षिकी मोड (एचएएम) पर मंज़ूरी दी है।

उत्तर प्रदेश भारत में शीर्ष इथेनॉल उत्पादक बनने के लिये तैयार

चर्चा में क्यों?

30 अक्टूबर, 2022 को उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव (चीनी उद्योग) संजय भूसरेड्डी ने मीडिया को बताया कि उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष इथेनॉल उत्पादक बनने के लिये तैयार है। राज्य में उद्योग का आकार 12,000 करोड़ रुपए को पार कर गया है।

प्रमुख बिंदु

- अतिरिक्त मुख्य सचिव (चीनी उद्योग) संजय भूसरेड्डी ने बताया कि उत्तर प्रदेश की इथेनॉल क्षमता 2 अरब लीटर प्रति वर्ष आँकी गई है, जो पाँच साल पहले 240 मिलियन लीटर प्रति वर्ष से लगभग आठ गुना अधिक है। अगले कुछ वर्षों में राज्य की इथेनॉल क्षमता 25 अरब लीटर प्रति वर्ष तक पहुँचने की उम्मीद है।
- उन्होंने बताया कि निजी क्षेत्र की डिस्टिलरीज ने पिछले पाँच वर्षों में राज्य की समग्र इथेनॉल क्षमता को उन्नत करने के लिये लगभग 7,500 करोड़ रुपए का निवेश किया है।
- राज्य सरकार किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने और इस क्षेत्र को चीनी बाज़ार की चक्रीय प्रकृति से बचाने के लिये गन्ने की फसल को एक आकर्षक इथेनॉल मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत करने का प्रयास कर रही है।
- संजय भूसरेड्डी ने कहा कि मौजूदा 2022-23 गन्ना पेराई सत्र में, पाँच निजी मिलें चीनी का उत्पादन किये बिना सीधे गन्ने के रस से इथेनॉल का निर्माण करेंगी। इसके अलावा, 71 अन्य मिलें बी-हैवी शीरे (B-heavy molasses) से इथेनॉल का उत्पादन करेंगी।
- इस बीच राज्य का गन्ना क्षेत्र 3 प्रतिशत या 84,000 हेक्टेयर बढ़कर 85 मिलियन हेक्टेयर से अधिक होने का अनुमान है, जबकि चालू सीजन में गन्ने का उत्पादन 2.35 करोड़ मीट्रिक टन होने का अनुमान है। वर्तमान गन्ना पेराई सत्र के दौरान कुल 120 चीनी मिलें- 93 निजी इकाइयाँ, 24 सहकारी इकाइयाँ और तीन उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम इकाइयाँ संचालित होंगी।
- विदित है कि 5 मिलियन से अधिक ग्रामीण परिवार उत्तर प्रदेश गन्ना क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जिसमें चीनी, इथेनॉल, गुड़, बिजली सह उत्पादन, गुड़, खांडसारी (अपरिष्कृत चीनी) आदि इसके उप-उत्पाद पोर्टफोलियो में शामिल हैं। प्रदेश में समेकित वार्षिक गन्ना अर्थव्यवस्था लगभग 50,000 करोड़ रुपए की है।